

सोने की कलम

प्रधान सम्पादक - चेतन गन्धे, 9893157809

आर.एन.आई. रजि. नं. 52089

Email - sonekikalam@gmail.com

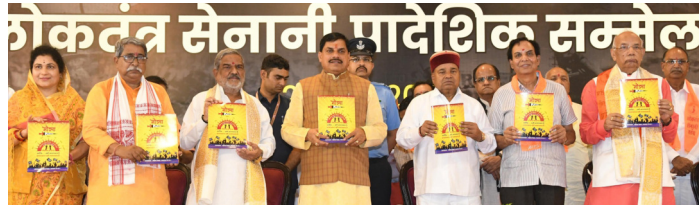


www.sonekikalamnews.com

लोकतंत्र हमारी जीवन शैली की है आत्मा - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लोकतंत्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह केवल एक शासन प्रणाली नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली की आत्मा और पहचान है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र भारतीय जनमानस में पुराकाल से रचा-बसा है और इसकी जड़ें हमारी परंपराओं में गहराई तक फैली हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती में लोकतंत्र सेनानियों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए कहा कि



हमारा वर्तमान लोकतंत्र उनके अनथक संघर्ष और बलिदान का ही परिणाम है। आज हम एक मजबूत और जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसके मूल में लोकतंत्र सेनानी ही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र शासन को जवाबदेह बनाता है, नागरिकों

को अधिकार देता है और प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली ही हमारी विविधता में एकता को बनाए रखने का आधार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी का आह्वान किया कि लोकतंत्र की इस विरासत को आगे बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है।

उन्होंने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।

दुनिया हमारी ओर हैरत से देखती है कि यहां लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। भारत देश सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का जनक है। उन्होंने कहा कि हम सब लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली विरोधी ताकतों से मिलकर लड़ेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के हित में घोषणा करते हुए कहा कि अब 70 साल से अधिक आयु के सभी लोकतंत्र सेनानियों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज और आवश्यकता पड़ने पर पीएम एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी।

भारत अड़ गया है, अब क्या करेंगे ट्रंप...

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटक गया है। 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले इस पर सहमति बनने की उम्मीद कम दिख रही है। दोनों देशों के बीच मुख्य असहमति ऑटो पार्ट्स, स्टील और कुछ कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन, मक्का, गेहूँ, इथेनॉल, डेयरी उत्पाद) पर आयात शुल्क को लेकर है।

अमेरिका इन पर भारत से टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है। जबकि भारत ग्रामीण रोजगार और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत इन पर टस से



मस होने को तैयार नहीं है। इस रवैये ने अमेरिका के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप बगले झांकते फिर रहे हैं। पहले ही चीन उन्हें टैरिफ के मसलों पर पटखनी दे चुका है। वह अपनी शर्तों से एक इंच पीछे नहीं हटा है। भारत भी समझौते को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वह एक संतुलित और आपसी फायदे वाली

डील चाहता है। भारतीय अधिकारी यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे अपनी शर्तों पर ही समझौता करेंगे। किसी भी समझौते पर तभी हस्ताक्षर किए जाएंगे जब उनकी अपेक्षाएं पूरी हों।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में रुकावट आ गई है। यह रुकावट ऑटो पार्ट्स, स्टील और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क को लेकर है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इस वजह से 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले कोई समझौता होने की उम्मीद कम है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई तक जवाबी शुल्क यानी रिसप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही है।

बंद कमरे में शिवराज और कैलाश की चर्चा



दोनों नेताओं ने की 18 मिनट बातचीत
केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री बाहर इंतजार करती रहीं

उद्योग, रोजगार का नया हब बनेगा ग्वालियर-चंबल-मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर-चंबल अंचल को एक बड़ी ट्रेन सुविधा उपलब्ध हुई है। अब अंचल के लोग ग्वालियर से ट्रेन द्वारा सीधे बंगलोर पहुंच सकेंगे। युवाओं के लिये यह विशेष तौर पर तोहफा है। साप्ताहिक ग्वालियर-बंगलोर ट्रेन सुविधा से आईटी के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे छात्र-छात्राओं को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर से गुरुवार को ग्वालियर से बंगलोर नई ट्रेन सुविधा का वचुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम से केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भी वचुअली जुड़े। ग्वालियर में आयोजित समारोह में



केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं रेलवे के अधिकारी

और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार से मध्यप्रदेश को रेल सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक सीमांतें मिली हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने रेलवे के क्षेत्र में विकास के कई आयाम छुए हैं। प्रदेश के लगभग 80 रेलवे स्टेशनों जिसमें ग्वालियर भी शामिल है, का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया के समय से ग्वालियर-अंचल को रेल सुविधाओं का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, उसी कड़ी में आज ग्वालियर से बंगलोर के लिये नई ट्रेन सुविधा मिली है।

इंदौर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 18 मिनट तक बंद में कमरे में चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर कमरे के बाहर खड़े होकर बैठक खत्म होने का इंतजार करती रहीं।

हालांकि दोनों सीनियर नेताओं ने अकेले में किस विषय पर चर्चा की, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि गुरुवार को इंदौर में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में हितग्राहियों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।

बैठक के दौरान विधायक मधु

वर्मा, मनोज पटेल और बीजेपी नेता सावन सोनकर पास के कमरे में बैठे हुए थे। जबकि राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर कमरे के बाहर इंतजार कर रही थीं। वहां मौजूद अधिकारियों ने जब सावित्री ठाकुर के इंतजार करने की सूचना दी तो शिवराज ने उन्हें 5 मिनट और इंतजार करने को कहा।

बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय दोनों नेता 3 बजकर 13 मिनट पर कमरे में गए थे। करीब 3 बजकर 30 मिनट यानी पूरे 18 मिनट बाद कमरे से बाहर आए। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर विजयवर्गीय ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान से सामान्य मुलाकात करने आया था।

अधिकारी मैदान में जाकर आँगनवाड़ी केन्द्रों की सतत निगरानी रखें- संभागायुक्त श्री सिंह

महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय बैठक सम्पन्न

◆इंदौर, सोने की कलम।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री डी.एस. रणदा, महिला एवं बाल विकास विभाग की क्षेत्रीय संयुक्त संचालक डॉ. संध्या व्यास, उप संचालक श्रीमती सुनीता यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा सहित संभाग के सभी जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संभाग में चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट देखी और उसकी समीक्षा की। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सभी अधिकारी मैदान पर जाकर आँगनवाड़ी केन्द्रों की निगरानी रखें। साथ ही यह भी



देखें कि आँगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों को जो पोषण आहार दिया जा रहा है वह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और आँगनवाड़ी सहायिकाएं समय पर आँगनवाड़ी केन्द्रों में पहुंचें और ठीक प्रकार से बच्चों की देखभाल करें। श्री सिंह ने कहा कि आलीराजपुर सहित बुरहानपुर और झाबुआ में कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिये विशेष प्रयास किये जायें। विशेषकर आलीराजपुर और इंदौर जिले में जो बच्चे पोषण पुनर्वास केन्द्र में अति गंभीर कुपोषित हैं उनके लिये विशेष कार्ययोजना बनाई जाये। बताया गया कि इंदौर संभाग में 17 हजार से अधिक

आँगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें सर्वाधिक तीन हजार 858 धार जिले में हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकर्ताओं के मानदेय, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने भी अपने सुझाव रखे।

बैठक में बताया गया कि धार जिले में तीन वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के ऐसे 105 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनके दिल में छेद है। इनमें से 40 बच्चों का ऑपरेशन इंदौर में मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत किया गया है।

30 जुलाई तक डूब प्रभावित क्षेत्रों में शिविर लगाकर विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करें- संभागायुक्त श्री सिंह

◆इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर। संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में संभागायुक्त कार्यालय में सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री डी.एस. रणदा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के श्री शैलेन्द्र सोलंकी, उप संचालक श्रीमती पूर्णिमा सिंघी, संभाग के जिलों के अनुविभागीय अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बड़वानी कलेक्टर एवं धार कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि धार और बड़वानी जिलों में इन दिनों औसत से अधिक वर्षा हो रही है। अतः इस क्षेत्र में विशेष

ध्यान देने की जरूरत है। आपदा की स्थिति में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, होमगार्ड विभाग, बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग आदि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। एनडीआरएफ की टीम होमगार्ड के जवानों और गोताखोरों को पूर्व प्रशिक्षण दें, ताकि आपदा की स्थिति में लोगों को बाढ़ आदि से बचाया जा सके। इसी माह में मॉकड्रिल का आयोजन भी कराया जाये।

संभागायुक्त श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति के पूर्व डूब क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जायें और उनके लिए आवास, भोजन, पानी, चिकित्सा आदि की वैकल्पिक व्यवस्था की जाये। मवेशियों के लिए भी चारा और चिकित्सा व्यवस्था की जाये।

शौर्यादल मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न

इंदौर। इंदौर जिले में शौर्यादल योजना के तहत किशोरी बालिकाओं की मास्टर ट्रेनर्स के लिये एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। इस प्रशिक्षण/कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रजनीश सिन्हा, प्रशासक वन स्टॉप सेंटर डॉ. वंचना सिंह परिहार, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति इंदौर श्रीमती पल्लवी पोरेवाल, बाल संरक्षण अधिकारी श्री अविनाश यादव, श्री भगवानदास साहू, श्री आशीष गोस्वामी, बाल विवाह कोर ग्रुप सदस्य श्री महेन्द्र पाठक आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में डॉ. वंचना सिंह परिहार द्वारा शौर्यादल के दायित्व एवं आत्मरक्षा कौशल निर्माण के बारे में शौर्यादल के सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी गई।

जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए,

जो अपमान करे उसे कभी बुलाना नहीं चाहिए !!

संपादकीय

आपातकाल के 50 साल छिनी प्रेस की आजादी

आजाद भारत के इतिहास में 25 जून को एक ऐसी घटना की 50 साल पूरे हो रहे हैं जिसमें 21 महीनों तक सत्ता का अतिरेक देखने को मिला था। उस अवधि में नागरिकों की संविधान प्रदत्त स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया था और विभिन्न संस्थानों की नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो गई थी। आपातकाल पर राष्ट्रपति, कैबिनेट और संसद ने मुहर लगाई थी। यह आपातकाल बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के खतरे के नाम पर लगाया गया था।

इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के पीठ के उस कुख्यात निर्णय से भी बल मिला जिसके तहत हैबियस कोर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता) जैसे मौलिक संरक्षण तक को निरस्त कर दिया गया था। कुल मिलाकर देखें तो जिन लोगों या संस्थाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना था उनके द्वारा इनके उल्लंघन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को प्रतिपक्षियों को असीमित अवधि तक हिरासत में रखने में मदद की। इसने प्रेस की आजादी को भी अभूतपूर्व तरीके से कुचले जाने की परिस्थितियाँ तैयार कीं।

संविधान के अनुच्छेद 352 की आड़ लेकर इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण का एक ऐसा कठोर कार्यक्रम आरंभ किया जिसने हजारों परिवारों के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया। उन्होंने झुगियों को तोड़ने की एक परियोजना भी चलाई जिसका नतीजा विरोध कर रहे रहवासियों को पुलिस द्वारा मारे जाने के रूप में सामने आया। मानवाधिकारों के हनन की यह कहानी अफसरशाही या निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा नहीं लिखी गई थी बल्कि यह इंदिरा गांधी के बेटे द्वारा असंवैधानिक शक्ति के प्रयोग से जन्मी थी। प्रेस पर लगे प्रतिबंधों तथा खबरों को गायब किए जाने के कारण देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इस बारे में ठीक से जान ही नहीं पाया।

ऐसे समय में जब प्रेस की आजादी को कुचलने के छिपे हुए प्रयासों की बात जोर पकड़ रही है, यह याद करना उचित है कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के इस चौथे खंभे पर किस कदर दबाव बनाया गया था और इसके क्या परिणाम हुए थे। उस समय जो दमनकारी गतिविधियाँ सामने आई थीं उनमें आपातकाल की घोषणा के महज कुछ घंटों के भीतर दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों के दफ्तरों-प्रेस की बिजली काट देने जैसी घटना शामिल थी ताकि उन्हें छपने से रोका जा सके।

आश्चर्य नहीं कि निरंतर दमन और दबाव के माहौल में जहाँ बिना जमानत के जेल भेज दिया जाना आम था, कई संपादकों ने सीमित प्रतिरोध की राह चुनी। जो अधिक साहसी थे, उन्होंने तानाशाही की सीमाओं को परखने का प्रयास किया। मिसाल के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने अभिव्यक्ति की आजादी के दमन के विरुद्ध मूक प्रतिरोध के रूप में अपने संपादकीय पन्ने को पूरी तरह खाली प्रकाशित कर दिया था।



चेतन गंधे
9893157809
सम्पादक

लाइनमैन बनने के लिए युवाओं ने थामी किट, लगाई दौड़ और झटपट चढ़े खंभे पर

बिजली कंपनी की भर्ती में दस्तावेज परीक्षण और शारीरिक परीक्षण जारी

◆इंदौर, सोने की कलम।

लाइनमैन समेत बिजली कंपनी के भर्ती अभियान में पोलोग्राउंड में लाइनमैन बनने के लिए मालवा और निमाड़ से उन युवाओं का जमावड़ा है, जिन्होंने एमपी ऑन लाइन के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में इन सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज परीक्षण और लाइनमैन के लिए अनिवार्य शारीरिक परीक्षण का दौर जारी है। यह शुक्रवार तक चलेगा।

पोलोग्राउंड इंदौर स्थित कंपनी मुख्यालय में दस्तावेज परीक्षण के साथ ही लाइनमैन के लिए जरूरी दौड़, पोल पर पंद्रह किलो वजन



लेकर चढ़ना और कार्य करना इत्यादि गतिविधियों को कराया जा रहा है। इसी के बाद शारीरिक परीक्षण में सफल माना जाता है। पोलोग्राउंड में मुख्य अभियंता कार्यालय के माध्यम से लाइनमैन भर्ती के लिए आए युवाओं को 15 किलो वजनी किट लेकर 10 मिनट में 1 किमी दौड़ने का परीक्षण हुआ। इसी के साथ 15 किलो वजनी किट लेकर 15 फीट ऊंचे पोल पर दो मिनट में चढ़ना और उतरने का परीक्षण भी इंजीनियरों की टीमों के समक्ष

हुआ। लाइनमैनों की किट में औसतन पंद्रह किलो वजन होता है, इनमें प्लायर, पेचकस, झूला, ग्लोबज, डिस्चार्ज राड, टेस्टर इत्यादि उपकरण/सामग्री होते हैं। मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर के समान ही परीक्षण का दौर उज्जैन स्थित रीजन कार्यालय में भी संपूर्ण प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। नेत्र परीक्षण भी कराए जा रहे हैं। दो दिनों में कंपनी स्तर पर लाइनमैन के लिए आए 160 से ज्यादा युवाओं का परीक्षण हुआ है।

जिले में क्षय रोग के लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग में लायें गति

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षय शिविर की प्रगति की समीक्षा की

◆इंदौर, सोने की कलम।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षय शिविर की बैठक आज कलेक्ट्रेट में सम्पन्न हुयी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, जिला क्षय अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र जैन, वरिष्ठ सर्जन डॉ. जी.एल. सोढी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने इंदौर जिले में चल रहे निक्षय शिविर की प्रगति रिपोर्ट देखी और उसकी समीक्षा की।

बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे इंदौर जिले में क्षय रोग के लक्षण वाले मरीजों की स्क्रीनिंग में गति लायें। वर्तमान में जितनी स्क्रीनिंग होना चाहिए थी, उस अनुपात में काफी कम है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर सर्वे करें और इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी



को दें। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर अपना कार्य ईमानदारी से करें और सर्वे की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें। श्री सिंह ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतेगा, नके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में करीब आठ लाख लोगों की स्क्रीनिंग होना है। इसमें ऐसे लोग शामिल है, जो बीते 5 साल से क्षय रोग के मरीज है, जो मधुमेह बीमारी से पीड़ित हैं, जो धूम्रपान करते हैं, कुपोषित हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। ऐसे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाना है।

सर्वे कार्य के लिये इंदौर में 18 केन्द्र बनाये गये हैं जहां सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के माध्यम से यह सर्वे का कार्य किया जा रहा है। यह सर्वे गत 20 मई से शुरू हुआ जो 100 दिन तक चलेगा। बैठक में बताया गया कि जो क्षय रोग के मरीज हैं उन्हें फूड बॉस्केट योजना के तहत फूड बॉस्केट दी जा रही है। वर्ष 2023 से लेकर अभी तक चार हजार मरीजों को फूड बॉस्केट दी जा चुकी है। फूड बॉस्केट निक्षय मित्र योजना के तहत दी जाती है। एक मरीज को अधिकतम 6 बार फूड बॉस्केट दी जाती है। बैठक में अधिकारियों ने भी अपने सुझाव और विचार रखे।

महाराष्ट्र के नागपुर में शिव कोदिया हुए पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित



समाज में जागृति लाने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है-- श्री प्रहलाद रजक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़

◆इंदौर, सोने की कलम।

रजक समाज के समाजसेवी व संपादक शिवनारायण कोदिया महाराष्ट्र के नागपुर में तेजस बहुउद्देशी संस्था द्वारा समाज सेवा व पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य करने पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक(राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) व सुप्रसिद्ध लोकगायिका श्रीमती रजनी रजक व समाजसेवी महेंद्र जी भूटानिया, श्री सुनील चोखरे इंडिया फेक न्यूज के संपादक नावेद अजमी तेजस बहुउद्देशी संस्था अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर अरगुलेवार, वरिष्ठ समाजसेवी जगन्नाथ जी फाले, देवदास पेटारे, के द्वारा श्री कोदिया को शाल श्री फल व सम्मान पत्र से पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री कोदिया ने बतलाया कि तेजस

बहुउद्देशीय संस्था व राष्ट्र संत गाडगे बाबा सेवा संघर्ष संघ द्वारा विगत 8 वर्षों से सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों से भी आये समाजसेवीयों व पत्रकार बंधुओं के साथ 10वीं 12वीं कक्षा में उत्रीण छात्र-छात्राओं का भी सम्मान किया गया। यह रजक समाज का राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र रजक संसार का भी मुख्य अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर संत श्री गाडगे बाबा को भारत सरकार से भारत रत्न से विभूषित किए जाने की मांग का सभी उपस्थित जनों ने समर्थन किया व संस्था द्वारा अक्टूबर माह में संपूर्ण भारत के रजकबंधुओं के साथ भारत रत्न की मांग को लेकर दिल्ली में बड़ा आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया।

दो दिवसीय जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ समापन - चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर लेंगे भाग



इन्दौर। वैज्ञानिक सोच को धरातल पर उतारने वाले ये बाल वैज्ञानिक आसमान को छुएंगे। बच्चों के द्वारा सामाजिक प्रतिबद्धता की अपनी अभूतपूर्व सोच को प्रदर्शित किया गया है। इंदौर में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी के समापन अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री विजय कुमार मण्डलोई द्वारा इन्हीं उदगारों से प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन और दीप प्रचलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एडीपीसी श्री नरेन्द्र जैन, प्राचार्य श्री कल्याण मार्केट वैष्णव बाल मन्दिर गर्ल्स हायर सेकंडरी स्कूल श्रीमती आभा जौहरी, ज्युरी सदस्य श्री सुमित रघुवंशी, श्रीमती अंजली सोनी, नोडल अधिकारी श्री आर के चेलानी, श्री मनोज खोपकर एवं समिति के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। प्रदर्शनी के संबंध में श्री राजकुमार चेलानी द्वारा इस सत्र से हायर सेकंडरी स्तर को भी मानक अपलोड करने की सुविधा की जानकारी देते हुए राज्य स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी गई।

म.प्र. सरकार देगी 94 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप, 4.3 लाख को साइकिल

भोपाल/इन्दौर। मध्यप्रदेश के करीब पांच लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप और साइकिल जुलाई के पहले ही हफ्ते में मिलने वाले हैं। सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 4 जुलाई से पहले स्कूटी, साइकिल और लैपटॉप के पात्र छात्रों का डेटा इकट्ठा कर शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, 4 लाख 30 हजार छात्रों को साइकिल मिलेगी जबकि 94 हजार छात्रों को लैपटॉप मिलने वाले हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार हर साल 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी देती है। वहीं, कक्षा 6वीं से 9वीं

4 जुलाई को किया जाएगा वितरण



तक के छात्रों को साइकिल दी जाती हैं। 2023-24 सत्र के छात्रों को एक साल बाद फरवरी 2025 में सरकार ने स्कूटी और लैपटॉप दिया था, जिसकी वजह से विपक्ष ने

सरकार की मंशा पर सवाल उठाए थे।

स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों का कहना है कि इस बार पर्याप्त बजट है, जिसकी वजह से छात्रों को समय पर लैपटॉप और साइकिल दी जा रही हैं। स्कूटी भी जुलाई में ही देने का प्लान है। इस साल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 74.48% रहा है। 71.37% छात्र और 77.55% छात्राएं पास हुई हैं। इनमें से ऐसे छात्र, जिन्होंने 75 फीसदी से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, उन्हें लैपटॉप मिलेगा जबकि हर सरकारी स्कूल के टॉप को स्कूटी मिलेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक अफसर ने

बताया कि जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसमें छात्र का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड का पता कर रहे हैं। 4 जुलाई से पहले इन सभी छात्रों का डेटा शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित छात्रों के बैंक खाते अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

इसी तरह 6वीं से 9वीं के ऐसे छात्र, जिन्होंने पहली बार एडमिशन लिया है, उन्हें साइकिल दी जाएगी। ऐसे छात्रों की संख्या करीब 4 लाख 30 हजार है। अफसरों के मुताबिक, 4 जुलाई को भोपाल के मिंटो हॉल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लैपटॉप और साइकिल बांटेंगे।

निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण करने पहुंचे महापौर

रहवासियों के साथ की चाय पर चर्चा, अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश



◆इंदौर, सोने की कलम।

गुरुवार को महापौर पुष्पमित्र भागवत ने वार्ड क्रमांक 43 में चल रहे विकास कामों का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने निर्माण कामों की गुणवत्ता, समय सीमा और स्थानीय आवश्यकताओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए कहा साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

महापौर ने स्थानीय रहवासियों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बातचीत की, जिसमें बीजेपी की नगर पालिक निगम सरकार द्वारा शहर में संचालित विभिन्न जनहितैषी योजनाओं एवं परियोजनाओं की जानकारी दी। लोगों ने भी सुझाव एवं समस्याएं साझा की, जिनका मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पार्षद दिनेश सोनगरा, एमआईसी सदस्य

राजेश उदावत, झोन अध्यक्ष पुष्पेंद्र पाटीदार, वार्ड अध्यक्ष दीपक बछेड़, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और रहवासी मौजूद रहे।

महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दिनों में निर्माण स्थलों पर विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था हो साथ ही कामों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न हो और सभी योजनाएं निर्धारित समयावधि में पूरी की जाएं।

एमजीएम मेडिकल होस्टल व्यवस्था में कसावट 2 दिन में पानी और बिजली व्यवस्था सुधारनी होगी

◆इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सभी मेडिकल होस्टल्स को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके तहत सारे 16 होस्टल्स के चीफ और असिस्टेंट वार्डन को बदला गया है।

दरअसल होस्टल्स में एमबीबीएस और पीजी छात्र स्टूडेंट्स रहते हैं लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण वे परेशान रहते थे और उचित माध्यम न होने के कारण परेशानी बनी रहती थी। इन समस्याओं में स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधाएं और अनुशासन खास हैं।

मामले में डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने शिकायत निवारण

के लिए और बेहतर व्यवस्था के मद्देनजर विभिन्न ब्लॉकों में नए सिरे से वार्डन नियुक्त किए हैं। इसके तहत सभी चीफ और असिस्टेंट वार्डन में बदलाव किया गया है। सभी वार्डन ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार भी संभाल लिया है।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी न आए इसलिए सभी वार्डन रोज उनसे बात कर परेशानी दूर करें व सभी होस्टल्स की समस्याओं में पानी और बिजली की व्यवस्था को दो दिन के अंदर तुरंत हल करने के निर्देश दिए हैं। नई ट्यूब लाइट्स, एलईडी बल्ब, सीएफएल लाइट लगवाई जा रही है ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बिना परमिट ऑटो पर सख्ती, रजिस्ट्रेशन होगा रद्द

इंदौर। इंदौर में बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे ऑटो रिक्शा पर अब परिवहन विभाग सख्ती बरतने जा रहा है। आरटीओ कार्यालय ने सभी ऑटो चालकों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तय समय में दस्तावेज पूरे न करने पर ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित या रद्द कर दिया जाएगा। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि हाल ही में की गई चेकिंग में यह सामने आया कि कई ऑटो मालिक वाहन खरीदते समय सभी जरूरी दस्तावेज और टैक्स जमा करके रजिस्ट्रेशन तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में न तो फिटनेस करवाते हैं और न ही परमिट लेते हैं।